

रजिस्टर्ड नं० एल०-३३-एस० एम० १३-१४/९७.



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, १८ अगस्त, १९९७/२७ श्रावण, १९१९

हिमाचल प्रदेश सरकार

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

अधिसूचना

सोलन,

संख्या ३-१६२/८२-सी० एस०-५०९०-६०४०.—पिछले सभी आदेशों व अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुये तथा हि० प्र० जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी निरोधक आदेश, १९७७ की धारा ३(१) (ई) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, बी० एस० नैन्टा, जिला दण्डाधिकारी, सोलन निम्नलिखित

वस्तुओं के सभी करों सहित प्रत्येक के समक्ष दर्शाये गये अधिकतम विक्रय मूल्य निर्धारित करता है:—

क्रम सं०	अनुसूची संख्या के अनुसार	वस्तु का नाम	थोक मूल्य	परचून मूल्य	
			₹0	₹0	
1.	2	1. ब्रैंड वजन 400 ग्राम (माडर्न)	5.25	5.80	प्रति ब्रैंड
		2. ब्रैंड वजन 800 ग्राम (माडर्न)	10.50	11.60	"
		3. ब्रैंड (बेकमैन, बोन, क्रीमिका तथा राज्य के बाहर से आने वाली अन्य) :			
		400 ग्राम	5.30	6.00	"
		800 ग्राम	10.60	12.00	"
2.	12	मांस/चिकन/मछली :			
		1. मीट बकरा	—	80.00	प्रति किलो
		2. ब्रायलर ड्रैस्ड	—	80.00	"
		3. चिकन ड्रैस्ड	—	70.00	"
		4. मीट सूअर	—	40.00	"
		5. कच्ची मछली	—	40.00	"
3.	18	दूध/दही/काटेज चीज :			
		1. बेरका दूध पैकड पाउच स्टैण्डर्ड (फैट 4.5 प्रतिशत व 8.5 प्रतिशत (एस0 एन0 एफ0) ।	13.50 6.75	लीटर आधा लीटर	14.00 7.00 लीटर आधा लीटर
		2. दूध टोण्ड (3.5 प्रतिशत फैट व 8.5 प्रतिशत एस0 एन0 एफ0) ।	11.50 5.75	लीटर आधा "	12.00 6.00 लीटर आधा लीटर
		3. दूध डबल टोण्ड (1.5 प्रतिशत फैट व 9 प्रतिशत एस0 एन0 एफ0) ।	10.00 5.00	लीटर आधा लीटर	10.50 5.25 लीटर आधा लीटर
		4. दूध स्कीमड (फैट 0.5 प्रतिशत व 8.7 प्रतिशत एस0 एन0 एफ0) ।	8.50 4.25	लीटर आधा लीटर	9.00 4.50 लीटर आधा लीटर
		5. दही	—	16.00	प्रति किलो
		6. पनीर कच्चा	—	60.00	प्रति किलो
4.	20	ठण्डे पेयजल :			
		1. बोतल वाले पेयजल (कैम्पा कोला) चिल्ड अन्य पेयजल (चिल्ड)	— —	7.00 8.00	प्रति बोतल " "
		2. सोडा	—	3.50	"

नोट.—सभी थोक विक्रेता/परचून विक्रेता ग्राहकों को उपरोक्त वस्तुओं की बिक्री के बिल/कैशमैमों देगा जिसकी डुप्लीकेट प्रति अपने रिकार्ड में निरीक्षण हेतु रखेगा ताकि सही भाव का पता चल सके ।

यह अधिसूचना पूरे सोलन जिला में हिमाचल प्रदेश राजपत्र में छपने के एक मास तक लागू मानी जायेगी।

बी० एम० नेन्टा,
जिला दण्डाधिकारी,
सोलन, जिला सोलन (हि० प्र०)।

Office of the District Magistrate, Shimla district, Himachal Pradesh

ORDER

Shimla, the 2nd August, 1997

No. SML-ALA/97-1211-1217.—Whereas it has been made to appear to me that a large number of Arms Licences as also the Fire Arms exists in Dodra Kwar Sub Division which results poaching of wild animals and birds oftenly including the breeding season.

Whereas this illegal act of poaching on the part of such people of Dodra Kwar poses a great threat to the environmental and ecological balance beside vanishing of valuable wild species and therefore this order should be passed *ex parte*.

Now therefore, I, Manisha Shridhar, District Magistrate, Shimla in exercise of the powers vested in me under section 144 Cr.P.C. do hereby order that all the licence holders in Dodra-Kwar Sub-Division will deposit their fire arms with the Sub-Divisional Magistrate, Dodra-Kwar for the period of sixty days because of breeding period w.e.f. 1st August, 1997 to 29th September, 1997.

This order shall come in force at once. This order shall not apply to Magistrates on duty/Military/Para Military/Police Force while on duty.

This order shall be published in the official gazette of Himachal Pradesh Government and publicity of the order shall also be made through All India Radio and Public Relations Department of the district and affixing the copies of order on the notice board of District Courts.

MANISHA SHRIDHAR,
District Magistrate, Shimla.

कार्यालय उपायुक्त, जिला सिरमोर, नाहन (हि० प्र०)

कारण बताओ नोटिस

नाहन-173001, 4 अगस्त, 1997

क्रमांक पी० एस०-2-मिस-126/79-4605-09.—जैसा कि जिला पंचायत अधिकारी, जिला सिरमोर द्वारा की गई प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट के आधार पर श्री मन्त राम, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत मखौली, विकास खण्ड

शिलाई, जिला सिरमौर निम्न आरोपों में संलिप्त एवं दोषी पाये गये। आरोपों का सार निम्न प्रकार से है :—

1. यह कि श्री अनिल कुमार पुत्र श्री मनी राम, ग्राम थुम्बाड़ी, तहसील शिलाई का जन्म, जन्म रजिस्टर प्रारूप-II हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु नियम 13 के अन्तर्गत, जन्म रजिस्टर में इन्द्राज नहीं है।
2. यह कि श्री अनिल कुमार पुत्र श्री मनी राम का इन्द्राज परिवार रजिस्टर के भाग-I पृष्ठ संख्या 52 क्र० सं० 10 पर इन्द्राज तो है लेकिन श्री अनिल कुमार की जन्म तिथि अंकित नहीं है।
3. यह कि श्री सन्त राम, उप-प्रधान द्वारा श्री अनिल कुमार पुत्र श्री मनी राम, ग्राम थुम्बाड़ी, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर का जन्म प्रमाण-पत्र 11-5-1991 जो परिवार रजिस्टर के आधार पर जारी किया गया है वह सरासर झूठा है व अनियमित है। अतः श्री सन्त राम द्वारा उप-प्रधान जैसे गरिमापूर्ण पद तथा शक्तियों का दुरुपयोग किया है।

अतः मैं, निशा सिंह, उपायुक्त, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 145 के अन्तर्गत यह कारण बताओ नोटिस जारी करती हूँ तथा श्री सन्त राम, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत सखौली, तहसील शिलाई को इस कारण बताओ नोटिस द्वारा निर्देश दिये जाते हैं कि जन्म प्रमाण-पत्र किस आधार पर जारी किया गया, जबकि उप-प्रधान द्वारा ऐसा कोई प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु न तो हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इससे यह स्पष्ट होता है कि आप द्वारा उप-प्रधान जैसे गरिमापूर्ण पद व शक्तियों का अनियमित रूप से दुरुपयोग किया। श्री सन्त राम, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत सखौली अपना स्पष्टीकरण इस कारण बताओ नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर-भीतर खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड शिलाई के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करें। निर्धारित अवधि के भीतर स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में आपके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। तथा आपको उप-प्रधान पद से निलम्बित करने बारे जेर धारा-145 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

नाहन-173001, 4 अगस्त, 1997

संख्या पी० एस०-2-मिस/126/79-4595-99.—जैसा कि ग्राम पंचायत सखौली के पंचायत पदाधिकारी द्वारा स्वेच्छा से ग्राम पंचायत की बैठकों से अनुपस्थित रहने के सम्बन्ध में उप-मण्डलाधिकारी (ना०), पावटा साहिब द्वारा की गई जांच अनुसार निम्न तथ्य दृष्टिगत हुये हैं :—

1. यह कि पंच श्रीमती छुमो देवी स्वेच्छा से दिनांक 8-10-96, 29-11-96 व 20-12-96 को पंचायत की लगातार तीन बैठकों से स्वेच्छा से अनुपस्थित रही। इसके अतिरिक्त उक्त पंचायत पदाधिकारी पंचायत बैठकों में अनुपस्थित होने पर भी पंचायत की कार्यवाही रजिस्टर में अपने हस्ताक्षर नहीं करते हैं। यह तथ्य ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी के ब्यानात से सिद्ध हो जाता है जिसके कारण कोरम पूरा नहीं होने के कारण ग्राम पंचायत कोई भी निर्णय लेने में असमर्थ है तथा विकासात्मक कार्य भी नहीं हो पा रहे हैं जोकि जन-प्रतिनिधित्व की भी अवमानना है। अतः उक्त कृत्य के लिए आप ग्राम पंचायत के सदस्य पद पर बने रहने योग्य नहीं हैं।

अतः इससे पूर्व कि इस कृत्य के लिये आपके विरुद्ध आगामी कार्यवाही की जाये, मैं, निशा सिंह, उपायुक्त, जिला सिरमौर, नाहन, हिमाचल प्रदेश आपको हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131 (1) (ख) (2) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी कर यह निर्देश देती हूँ कि वे इस नोटिस की प्राप्ति के 15 दिन के भीतर-भीतर उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड शिलाई के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित करें। स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में यह

समझा जायेगा कि आप दोनों को सही मानते हैं तथा आपके विरुद्ध अधिनियम, 1994 की धारा 131 के अन्तर्गत एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

नाहन-173001, 4 अगस्त, 1997

संख्या पी0 एस0-2-मिस0/126/79-4600-04.—जैसा कि ग्राम पंचायत सखौली के पंचायत पदाधिकारी द्वारा स्वेच्छा से ग्राम पंचायत की बैठकों में अनुपस्थित रहने के सम्बन्ध में उप-मण्डलाधिकारी (ना0), पावटा साहिब द्वारा की गई जांच अनुसार निम्न तथ्य दृष्टिगत हुये हैं:—

1. यह कि पंच श्रीमती मनसा देवी स्वेच्छा से दिनांक 8-10-96, 29-11-96 व 20-12-96 को पंचायत की लगातार तीन बैठकों में स्वेच्छा से अनुपस्थित रही। इसके अतिरिक्त उक्त पंचायत पदाधिकारी पंचायत बैठकों में उपस्थित होने पर भी पंचायत की कार्यवाही रजिस्टर में अपने हस्ताक्षर नहीं करते हैं। यह तथ्य ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारों के व्यापार में पिछे हो जाता है जिसके कारण कोरम पूरा न होने के कारण ग्राम पंचायत कोई भी निर्णय लेने में असमर्थ है तथा विकासात्मक कार्य भी नहीं हो पा रहे हैं जोकि जन-प्रतिनिधित्व की भी अवमानना है। अतः उक्त कृत्य के लिये आप ग्राम पंचायत के सदस्य पद पर बने रहने के योग्य नहीं हैं।

अतः इससे पूर्व की इस कृत्य के लिये आपके विरुद्ध आगामी कार्यवाही की जाये, मैं, निशा सिंह, उपायुक्त, जिला सिरमौर, नाहन (हि0 प्र0) आपको हि0 प्र0 पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा 131 (1) (ख) (2) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी कर यह निर्देश देती हूँ कि वे इस नोटिस की प्राप्ति के 15 दिन के भीतर-भीतर उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण, खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड शिलाई के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित करें। स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जायेगा कि आप दोनों को सही मानते हैं तथा आपके विरुद्ध अधिनियम, 1994 की धारा 131 के अन्तर्गत एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

निशा सिंह,
उपायुक्त,
जिला सिरमौर, नाहन (हि0 प्र0)।

